

पत्रांक: जी.एस.टी./2019-20/

73 / 192001)

/वाणिज्य कर

कार्यालय- कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक: २५ अप्रैल, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1
एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) / (वि०अनु०शा०)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- परिवहन के दौरान वस्तुओं एवं वाहन को जाँच हेतु रोकने, अभिरक्षा, मुक्ति एवं जब्ती की प्रक्रिया के सम्बन्ध में सचल दल अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र सं०- 229 दिनांक 09.05.2018 में संशोधन के सम्बन्ध में।

परिवहन के दौरान वस्तुओं की जाँच हेतु वाहनों को रोकने तथा ऐसे माल एवं वाहनों की अभिरक्षा, मुक्ति और जब्ती हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ इन्डायरेक्ट टैक्सेस एण्ड कस्टम द्वारा परिपत्र सं०- 41/15/2018-जी.एस.टी. दिनांक 13.04.2018 जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में सचल दल अनुभाग द्वारा परिपत्र सं०- 229 दिनांक 09.05.2018 जारी किया गया है।

2. उपरोक्त प्रक्रिया में कुछ विषयों में स्पष्टीकरण हेतु उपरोक्त परिपत्र सं०- 229 दिनांक 09.05.2018 में निम्नलिखित संशोधन जारी किये जा रहे हैं -

(i) उक्त परिपत्र के पैरा 2(e) में वाक्य "तीन कार्य दिवस" को "तीन दिवस" से रिप्लेस किया जाता है।

(ii) उक्त परिपत्र के पैरा तीन के बाद FORM GST MOV-05 निम्न प्रकार पढ़ा जायेगा -

"उपरोक्त के सापेक्ष, वस्तुएं तथा वाहन (DD/MM/YYYY) ___AM/PM पर मुक्त किये जाते हैं।"

3.0 उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम-138C(2) के अनुसार यदि परिवहन के दौरान राज्य में किसी एक स्थान पर वस्तु एवं वाहन की जाँच हो चुकी हो तो उसका अन्य कोई भौतिक सत्यापन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि करापवंचन से सम्बन्धित कोई ठोस सूचना उपलब्ध न हो। चूँकि जरूरी फॉर्मस कॉमन पोर्टल पर वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं। अतः स्टेट टैक्स ऑफिसर्स अथवा सेन्ट्रल टैक्स ऑफिसर्स द्वारा प्रारम्भ की गयी जाँच की सूचना एक दूसरे को नहीं मिल पाती। ऐसी स्थितियों में प्रक्रिया के सम्बन्ध में संदेह बना रहता है।


3.1 इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी टैक्स अथॉरिटी द्वारा निश्चित फॉर्म्स पर निर्गत किये गये नोटिसों/आदेशों की हार्ड कॉपी आवश्यकतानुसार दूसरे टैक्स अथॉरिटी को कार्यवाही प्रारम्भ होने के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

3.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि सिर्फ़ ऐसी वस्तुएं और/अथवा वाहन को रोका/जब्त किया जायेगा जो कि जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधानों अथवा नियम का उल्लंघन करते हों।

उदाहरण:- जहाँ पर किसी ऐसे वाहन को रोका जाता है जो कि 25 कन्साइनमेन्ट ले जा रहा हो और ऐसे वाहन का Person-In-charge रोके जाने पर 20 कन्साइनमेन्ट के सम्बन्ध में सही ई-वे बिल और/अथवा जरूरी प्रपत्र दे देता है, परन्तु शेष पाँच के लिए जरूरी प्रपत्र नहीं दे पाता है, वहाँ पर केवल उन पाँच कन्साइनमेन्ट तथा वाहन के सम्बन्ध में ही डिटेन्सन/जब्ती की जा सकती है।

निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार जारी किये जा रहे प्रक्रियात्मक निर्देशों का प्रचार-प्रसार कराते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय,



(विवेक कुमार)

एडीशनल कमिश्नर (जी०एस०टी०)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

F. No. CBEC/20/16/03/2017-GST
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Indirect Taxes and Customs
GST Policy Wing

New Delhi, Dated the 21st June, 2018

To,

The Principal Chief Commissioners / Chief Commissioners / Principal Commissioners / Commissioners of Central Tax (All) / The Principal Directors General / Directors General (All)

Madam/Sir,

Subject: Modifications to the procedure for interception of conveyances for inspection of goods in movement, and detention, release and confiscation of such goods and conveyances, as clarified in Circular No. 41/15/2018-GST dated 13.04.2018 –reg.

Circular No. 41/15/2018-GST dated 13.04.2018 was issued to clarify the procedure for interception of conveyances for inspection of goods in movement, and detention, release and confiscation of such goods and conveyances.

2. In order to clarify certain issues regarding the specified procedure in this regard and in order to ensure uniform implementation of the provisions of the CGST Act across all the field formations, the Board, in exercise of the powers conferred under section 168 (1) of the Central Goods and Services Tax Act, hereby issues the following modifications to the said Circular:-

- (i) In para 2 (e) of the said Circular, the expression “three working days” may be replaced by the expression “three days”;
- (ii) The statement after paragraph 3 in **FORM GST MOV-05** should read as: “In view of the above, the goods and conveyance(s) are hereby released on (DD/MM/YYYY) at ___ AM/PM.”

3.0 Further, it is stated that as per rule 138C (2) of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, where the physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place within a State or Union territory or in any other State or Union territory, no further physical verification of the said conveyance shall be

carried out again in the State or Union territory, unless a specific information relating to evasion of tax is made available subsequently. Since the requisite FORMS are not available on the common portal currently, any action initiated by the State tax officers is not being intimated to the central tax officers and *vice-versa*, doubts have been raised as to the procedure to be followed in such situations.

3.1 In this regard, it is clarified that the hard copies of the notices/orders issued in the specified FORMS by a tax authority may be shown as proof of initiation of action by a tax authority by the transporter/registered person to another tax authority as and when required.

3.2 Further, it is clarified that only such goods and/or conveyances should be detained/confiscated in respect of which there is a violation of the provisions of the GST Acts or the rules made thereunder.

Illustration: Where a conveyance carrying twenty-five consignments is intercepted and the person-in-charge of such conveyance produces valid e-way bills and/or other relevant documents in respect of twenty consignments, but is unable to produce the same with respect to the remaining five consignments, detention/confiscation can be made only with respect to the five consignments and the conveyance in respect of which the violation of the Act or the rules made thereunder has been established by the proper officer.

4. It is requested that suitable trade notices may be issued to publicise the contents of this Circular.

5. Difficulties, if any, in implementation of the above instructions may be brought to the notice of the Board at an early date. Hindi version will follow.

(Upender Gupta)
Commissioner (GST)